>

Title : Need to supply petroleum coke to local industrial units from

Barauni Petroleum Refinery, Bihar on priority basis.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना हेतु बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार की पहल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्वीकृति दी थी। असम से पाइप के द्वारा कच्चे तेल को संस्कारित करना इसके साथ ही इसकी नेप्था से 34 पैट्रो केमिकल एवं एरोमेटिक कारखाने 31 राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे भागलपुर के नौगछिया तक लगना था। देश और बिहार के लाखों नवयुवकों को रोजी-रोटी की व्यवस्था इसके माध्यम से होनी थी। बरौनी को ब्रिटेन का लंकाशायर बनना था पर विडम्बना यह है कि रिफाइनरी की नेप्था से जो कारखाने लगने थे उसमें से एक खाद कारखाना किसी तरह लग पाया था जो वर्षों से आज तक बंद है। इसका नेप्था, मुम्बई और जर्मनी तक वहां के कारखाने को कच्चे माल के रूप में दिया जा रहा है। भारत सरकार की घोर उपेक्षा ने बिहार के औद्योगिकीकरण को रोका, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी होना था लेकिन वह नहीं हो पाया। एक से एक घातक प्रहार भारत सरकार की ओर से बिहार के औद्योगिकीकरण पर किए जा रहे हैं। बिहार औद्योगिकीकरण के लिए किसी तारणहार की तलाश में है।

पहले तमाम कन्सांइट पैट्रोलियम कोक को बनाने वाली छोटी-मोटी कंपनियों को उसकी उत्पादकता के आधार पर पैट्रो कोक कच्चे माल के रूप में आवंटित हुआ करता था। अब यह प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। अब पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पैट्रो कोक को खुली डाक बोली के सहारे इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनियां कच्चे माल को उठा लेंगी और फिर ऊंचे दाम देने वाली कंपनियों को अपनी ओर से कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। इस प्रक्रिया को अपनाने से बरौनी रिफाइनरी पर आधारित औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे और इस पर आधारित हजारों कामगार बेकार हो जाएंगे और सैकड़ों करोड़ रूपये की लगी हुई पूंजी बर्बाद हो जाएगी। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि बरौनी रिफाइनरी की नेप्था पर आधारित जितनी स्थानीय कंपनियां पेट्रो कोक के कच्चे माल पर आधारित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले आपूर्ति की जाती थी अब भी कहने के लिए यह प्राथमिकता की बात की जाती है पर डाक बोली के आधार पर आवंटन से व्यवहार में प्राथमिकता नहीं रह पाएगी। अतः भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हमारी मांग है कि वह पैट्रो कोक कच्चे माल का आवंटन उसका निस्तारण पूर्व की प्रक्रिया के आधार पर चलाए ताकि यह नई प्रक्रिया अव्यवस्था न बने और औद्योगिकीकरण पर नकारात्मक प्रभाव न हो। अतः इस नए कदम को वापस करे और पूर्व के नियम प्रक्रिया को ही आवंटन का आधार बनाकर रखे। इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।